Titupati Balaji Group / Established 2009 / Ghaziabad
R.N.I No. UPBIL/2009/28691, DAVP Code: 101473

Page 8 / Price Rs. 2.00 / Ghaziabad, Sunday, 1 July 2018
Postal Registration No. UP/GBZ-80/2016-18

TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

Vol./Year-10 Issue - 4

Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad
केन्द्र एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

www.tbcgzb.com

News of the Week देश को झकझोर देने वाले बुराड़ी सामूहिक मौत कांड का राज अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण से खुलेगा। जांच में जुटी दिल्ली की क्राइम ब्रांच मरने वाले सभी 11 लोगों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना चाहती है।

Inside Ghaziabad

पेज नंबर 2
जीडीए में तीन कर्मचारियों के खिलाफ होगी जांच

पेज नंबर 5
Front wheel hanging over edge, Noida school...

TIRUPATIEYE

कैंसर पर जागरूकता कार्यक्रम 8 जुलाई को

गाजियाबाद : रोटरी डिस्ट्रिक 3012 के 11 क्लब व मैक्स अस्पताल वैशाली द्वारा ऑरल, थ्रोट, ब्रेस्ट व सरवाईकल कैंसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैक्स अस्पताल में 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक हेल्थ टॉक से जानकारी दी जाएगी। इस बात की जानकारी रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर के चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव ने दी।

दस तक होंगे राशन कार्ड के लिए आवेदन

गाजियाबाद : शासन के आदेश पर जिलापूर्ति विभाग ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलापूर्ति अधिकारी सुनील ड्क्षसह ने बताया कि पात्र व्यक्तियों के राशनकार्ड शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के सपोक्ष में 64.43 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में बनाए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में ई–प्रणाली के जरिए पात्र व्यक्तियों को क्षेत्रीय खाद्य कार्यालयों और तहसीलों से दिए जाते हैं।

बारह झोलाछाप डाक्टरों को नोटिस

गाजियाबाद : स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ बुधवार को अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने खोड़ा क्षेत्र में 12 डाक्टरों को नोटिस देते हुए सीएमओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संबंधित कागजात उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। औचक निरीक्षण के दौरान कहीं किसी क्लीनिक पर डाक्टर नहीं मिले तो कहीं तो उनके परिवार वाले मिले। इन सभी को नोटिस दिया गया और तीन दिन में जवाब मांगा गया है।

रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने बांटी 235 यूनिफार्म

प्राथमिक विद्यालय साहिबाबाद में किया गया ड्रेस वितरण समारोह का आयोजन

साहिबाबाद : रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर द्वारा प्राथमिक विद्यालय साहिबाबाद में बुधवार को यूनिफार्म वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रोटरी क्लब व मुख्य अतिथि पार्षद हिमांशु चौधरी ने विद्यालय के सभी 235 विद्यार्थियों को यूनिफार्म बांटी। जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर की आईपीपी रो. मनीषा भार्गव ने बताया कि हमारा उद्देश्य इस स्कूल को स्मार्ट स्कूल की तर्ज पर विकसित करना है। इसके लिए स्कूल में दो कंप्यूटर व एक प्रोजेक्टर के अलावा 12 पंखे, पानी की टंकी की व्यवस्था, सबमर्सिबल की सुविधा भी पूर्व में की जा चुकी है। वहीं क्लब के चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव ने कहा कि 2 जुलाई से स्कूल खुल गए थे लेकिन बच्चों के पास यूनिफार्म नहीं थी जिसके कारण सभी बच्चों को यूनिफार्म वितरित की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का ज्ञान भी अब बहुत जरूरी हो गया है इसके लिए स्कूल को दो कंप्यूटर व एक प्रोजेक्टर दिए गए थे। जिससे यहां के बच्चे भी कान्वेंट स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई कर सके। इस दौरान प्रधानाचार्या मंजू रावत व अन्य अध्यापक मौजूद थे।

डा.धीरज बेस्ट रोटेरियन व मनीषा भार्गव प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित

गाजियाबाद : रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर की अध्यक्ष रो. मनीषा भार्गव को प्लेटिनम प्रेजीडेंट व चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव को बेस्ट रोटेरियन अवार्ड वर्ष 2017–18 डिस्ट्रिक 3012 से सम्मानित किया गया। रेडीसन ब्लू होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों को डिस्ट्रिक गवर्नर रो.सतीश सिंघल ने सम्मानित किया। वहीं रो. संजीव भार्गव को भी प्लेटिनम सैकेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। डा. धीरज भार्गव ने बताया कि उनके क्लब को प्लेटिनम अवार्ड, प्लेटिनम प्रेजीडेंट व प्लेटिनम सैकेटरी अवार्ड लगातार दूसरी बार दिया गया है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक 3012 के 87 क्लब व लगभग 2500 मैंबर के बीच बेस्ट रोटेरियन के अलावा क्लब को कई अवार्ड मिलना मेरे लिए खुशी की बात है और यह सम्मान सभी रोटेरियन के सहयोग से मिल पाया है। मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

Regional flights to 4 cities including Kannur and Hubli from Hindon airbase expected by October end

Ghaziabad : If all goes well, passengers to Kannur in Kerala, Hubli in Karnataka, Nashik in Maharashtra and Pithoragarh in Uttarakhand will have a direct air link from Ghaziabad by October-end. Officials of the Ghaziabad district administration are hopeful that the regional flights from the Hindon airbase can start from October this year. The airbase has been selected for operation of regional flights under the regional connectivity scheme of the Union ministry of civil aviation. The scheme will provide relief to the overburdened Delhi airport. Ghaziabad district magistrate Ritu Maheshwari has been nominated as the nodal officer for taking decisions on lease agreement with farmers and other infrastructure facilities, which are to be developed as part of the project. She said a draft of the memorandum of understanding (MoU) has been finalised and sent to the state government. "The MoU is to be signed between the UP government and the Airports Authority of India (AAI), which will develop the terminal facilities under the project. The infrastructure facilities such as connecting road and electricity supply will be provided by the UP agencies.

जीडीए में तीन कर्मचारियों के खिलाफ होगी जांच

गाजियाबाद : स्वर्णजयंतीपुरम प्लॉट पुनःआवंटन घोटाले में आरोपित लेखा अनुभाग के कर्मचारी सुरेंद्र कौशिक, प्रभात कुमार और सेवानिवृत अजय त्यागी के खिलाफ जीडीए में ही जांच होगी। शासन ने जीडीए उपाध्यक्ष को इस संबंध में पत्र भेजा है। यह कहा है कि तीनों की भर्ती जीडीए स्तर से हुई थी। लिहाजा इनकी जांच शासन नहीं कर सकता। जीडीए से ही होगी। इस मामले में जांच कमेटी बनाई जाएगी। स्वर्णजयंतीपुरम में 1998 से 2003 के बीच ग्यारह योजनाएं घोषित हुई थीं। जिसमें 1583 भूखंडों के आवंटन किए गए। किश्तों का भुगतान न होने और कुछ के परित्याग करने के कारण आवंटन निरस्त किए गए थे। फरवरी 2005 से फरवरी 2007 के बीच जीडीए ने उनमें से 137 प्लॉटों को दोबारा आवंटित कर दिया गया। प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य होने के नाते पार्षद राजेंद्र त्यागी ने एक शिकायती चिट्ठी के आधार पर 2007 में दोबारा आवंटन पर सवालिया निशान लगाए थे। इस मामले की जांच में पूर्व वीसी डीपी ड्क्षसह और पूर्व ओएसडी हीरालाल समेत आठ कर्मचारी आरोपित हैं। इनके खिलाफ आरोप पत्र शासन को जा चुका है।

झगड़ा कर रहे दो युवक गिरफ्तार

गाजियाबाद : मुरादनगर की मोहल्ला कोट कॉलोनी में बुधवार रात को कमेटी के पैसे लेकर दो युवकों में जमकर लात घूसे चले। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनका शांतिभंग की धाराओं में चालान कर दिया है। कोट कॉलोनी निवासी रहीसुद्दीन व इमरान कमेटी डालते हैं। बुधवार रात दोनों के बीच कमेटी के पैसे को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच जमकर लात घुसे चले। इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रहीसुद्दीन व इमरान को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया।

जीडीए इंदिरापुरम और राजनगर एक्सटेंशन में हटाएगा अतिक्रमण

गाजियाबाद : इंदिरापुरम और राजनगर एक्सटेंशन में लोग अतिक्रमण से परेशान हैं। वार्ड–99 के पार्षद अभिवन जैन सहित कई लोगों ने जीडीए में इस संबंध में शिकायत दी है। जीडीए ने आश्वासन दिया है कि अगले सप्ताह से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इंदिरापुरम और राजनगर एक्सटेंशन जीडीए के जिम्मे है। यहां की सफाई व्यवस्था और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखना इनकी जिम्मेदारी है। लापरवाही के कारण दोनों क्षेत्रों में हरित पट्टियों और सड़क किनारे अतिक्रमण बढ़ रहा है। जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क से गुजरने वाले जाम की समस्या झेल रहे हैं। पार्षद ने अपनी शिकायत में कहा है कि इंदिरापुरम के वैभवखंड में कुछ लोगों ने मार्केट के ओपन क्षेत्र में कुर्सी–मेज डालकर आसपास कई दुकानें खोल ली हैं। वहां बैठकर लोग शराब पीते हैं। जीडीए ओएसडी वीके सिंह ने बताया कि इंदिरापुरम और राजनगर क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण की शिकायत मिल रही है। जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जिससे लोगों की परेशानी कम हो।

दो जनसूचना अधिकारियों पर लगाया 25–25 हजार जुर्माना

गाजियाबाद : राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम और जिला अधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी पर 25–25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ड्क्षचरजीव विहार निवासी वेदप्रकाश अग्रवाल ने नगर निगम से सात बिंदुओं पर वर्ष 2016 में सूचनाएं मांगी थीं। डस्टबिन कहां लगवाए गए, किस दर पर उनकी खरीद हुई, डस्टबिन का आकार क्या है? इस समेत कई सवाल पूछे थे। जिनका जवाब नहीं मिला। अपील दायर करने पर भी जवाब नहीं मिला। ऐसे ही जिला अधिकारी कार्यालय से चिरंजीव विहार सेक्टर–दो व तीन की समस्याओं से संबंधित 207 शिकायतों से जुड़ी जानकारी तीन प्रश्नों के माध्यम से मांगी थी।

डूडा ने ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का किया सत्यापन तो निकली चौकाने वाली जानकारी, कई आवंटन होंगे निरस्त

गाजियाबाद : इंटिग्रेटिड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आइएचएसडीपी) के तहत बनाए गए ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रह रहे लोगों का सत्यापन डूडा ने शुरू कर दिया है। जिस फ्लैट में मूल आवंटी नहीं पाए जा रहे, उनका आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई होगी। सत्यापन के शुरुआत में ही एक मामला सुदामापुरी लाला क्वार्टर में सामने आया है। मूल आवंटी तीन लाख रुपये में फ्लैट बेच कर चला गया। उसकी जगह दूसरा परिवार वहां रह रहा है। इस कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डूडा को वर्ष 2006 में 1236 लाल क्वार्टर बनाने की केंद्र और राज्य सरकार से अनुमति मिली थी। इस योजना

पर 1836 करोड़ रुपये की लागत आई। वर्ष 2011–12 में क्वार्टर बनकर तैयार हो गए। लाल रंग के होने के कारण इनका नाम लाल क्वार्टर पड़ गया। झुग्गी में रहने वाले लोगों को दो कमरे का ईडब्ल्यूएस मकान आवंटित कर दिया गया। इसी योजना के तहत 2008 में अर्थला में 208 फ्लैट बनाने की स्वीकृति शासन ने दी। पिछले साल ही इनमें आवंटन हुआ है। पिछले महीने डासना में इसी योजना के तहत तैयार हुए 204 फ्लैट में आवंटन किए गए। अब डूडा तो मालूम हुआ कि जिन्हें फ्लैट आवंटित किए गए, वह वहां नहीं रह रहे। उनकी जगह कोई और फ्लैट में रह रहा है। इस शिकायत पर डूडा ने सुदामापुरी लाल क्वार्टर से सत्यापन शुरू कर दिया है। जिसमें शिकायत सही पाई गई है। मूल आवंटी अपना फ्लैट दूसरे को बेच कर चला गया। उस फ्लैट में दूसरा परिवार रह रहा है। कई फ्लैट लोग में किराय पर लोग रह रहे हैं। डूडा अधिकारियों के मुताबिक आवंटी को दिए गए आवंटन पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि वह फ्लैट को बेच नहीं सकते और किराय पर नहीं दे सकते। ऐसा करने पर आवंटन निरस्त किया जाएगा। इस शर्त का उल्लंघन करने वालों के आवंटन निरस्त किए जाएंगे।

अगस्त में शुरू होगा डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन का काम

गाजियाबाद : नगर निगम अगले महीने तक बचे हुए 18 वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन शुरू कर देगा। इसके लिए टेंडर की शर्तें निर्धारित करने का कार्य शुरू हो गया है। इस महीने तक ठेका छोड़ दिया जाएगा। ऐसा होने के बाद निगम क्षेत्र के प्रत्येक घर से कूड़ा उठना सुनिश्चित हो जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में सौ वार्ड हैं। इनमें से 82 वार्डों में ही डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन की सेवा पिछले छह महीने से चल रही है। जिन वार्डों में यह सेवा नहीं है। वह मांग कर रहे हैं कि उनके यहां प्रत्येक घर से कूड़ा उठवाया जाए। उस आधार पर उन वार्डों में नगर निगम डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन सेवा देने के लिए प्रयास शुरू हुए हैं।

टेलीमेडिसिन सेवा से लैस होंगे हेल्थ सेंटर

गाजियाबाद : ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए टेलीमेडिसिन सेवा और मोबाइल हेल्थ यूनिट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली विश फाउंडेशन इंडिया के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार को एक प्रपोजल बनाकर डीएम को सौंपा है। संस्था लोनी तहसील के प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर मेडिसिन वेंडिंग मशीन और वीडियो क्रांफेसिंग के जरिए दूरस्थ विशेषज्ञ डाक्टरों से उपचार कराने का प्रस्ताव रखा है। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीज की स्क्रीनिंग के लिए नेट से कनेक्ट क्योस्क मशीन लगाने की पेसकश की है। इस काम में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान बताया गया है। आज भी गांवों में बेहतर इलाज का बेहद अभाव है। विशेषज्ञ डाक्टरों एवं संशाधनों की कमी के चलते लोगों को कोसों दूर शहर और महानगर इलाज के लिए जाना पड़ता है। सरकार लोगों को मौके पर बेहतर इलाज कराने के लिए प्रयासरत है। जिले के लोनी ब्लाक के सभी सरकारी मेडिकल सेंटरों की सेवा को बेहतर बनाने में सहयोग देने की संस्था की पेसकश पर प्रशासन की ओर से विचार किया जा रहा है।

घर के सामने पालतु कुत्ते ने गंदगी की तो चले लाठी डंडे

गाजियाबाद : मुरादनगर की बीचपटा कॉलोनी में घर के सामने पालतु कुत्ते द्वारा गंदगी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बीचपटा कॉलोनी निवासी ब्रजमोहन सिंह कुत्ता पालते हैं। बृहस्पतिवार सुबह वह अपने कुत्ते को घूमा रहे थे। इसी बीच कुत्ते ने गली में रहने वाले गंगाराम के घर के सामने गंदगी कर दी। इस बात को लेकर ब्रजमोहन व गंगाराम के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले।

यशोदा फाउंडेशन से 18.50 लाख रुपये की होगी रिकवरी

गाजियाबाद : नेहरूनगर स्थित कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बगैर किरायानामा रजिस्टर्ड यशोदा फाउंडेशन को देने और सालों से किराया न वसूलने के मामले में जीडीए ने जांच पहले ही शुरू दी थी। अब 18.50 लाख रुपये की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। हॉस्टल का कब्जा वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। पार्षद राजेंद्र त्यागी ने आरोप लगाया था कि जीडीए ने नियमों का उल्लंघन कर किरायानामा रजिस्टर्ड कराए बगैर 2010 में हॉस्टल यशोदा फाउंडेशन को दे दिया। यह आरोप भी लगाया कि फाउंडेशन ने एक साल का किराया अदा किया। बाद आठ साल से किराया लिए बगैर हॉस्टल उनके कब्जे में दे रखा है। किराया वसूली के लिए एक भी नोटिस फाउंडेशन को नहीं भेजा गया। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही के कारण 21 लाख 90 हजार 552 रुपये का नुकसान जीडीए को हुआ है। बकाया पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज भी तय था, जो नहीं मिला। उस पर जांच शुरू होने के बाद जीडीए ने रिकवरी नोटिस जारी कर दिया है। संपत्ति अनुभाग को हॉस्टल का कब्जा वापस लेने के निर्देश दिए हैं।

म्यूचुअल फंड में करें निवेश, पाएं बेहतर लाभ : संजय नारंग

आरडीसी राजनगर स्थित एडीआर होटल में फाइनेंसियल इनवेस्टमेंट पर सेमिनार का हुआ आयोजन

रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर व एचडीएफसी म्युचुअल फंड ने मिलकर किया कार्यक्रम का आयोजन

गाजियाबाद : रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर व एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा शनिवार को राजनगर स्थित एडीआर होटल में फाइनेंसियल इनवेस्टमेंट पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश से होने वाले फायदे के बारे में बताया गया। इस दौरान लोगों ने निवेश से संबंधित सवाल–जवाब भी किए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के संजय नारंग ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से डरते हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड का पैसा भी बाजार में ही लगता है लेकिन इसमें ये काम आपके लिए एक जानकार करता है जिससे जोखिम काफी कम हो जाता है। सेमिनार को संबोधित करते हुए रोटेरियन अमित कंसल ने कहा कि यदि आप अपने पैसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते देखना चाहते है तो म्यूचुअल फंड में निवेश करें। डायरेक्ट इनवेस्टमेंट की सबसे बडी खासियत यह है कि आप अपने पोर्टफोलियोपर खुद नजर रख सकते हैं। यदि आपने रिसर्च कर अपने लिए कुछ फंड चुने हैं तो आप खुद बाय या पर्चेज कर सकते है। आप चाहें तो इन फंड कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सलाह की भी मदद ले सकते है। डायरेक्ट इनवेस्टमेंट में निवेशक को सब कुछ खुद करना होता है। जिसके कारण कुछ परेशानियां भी आती है। इस दौरान रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर की आईपीपी रो.मनीषा भार्गव, चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव, कुनिका भार्गव, प्रतीक भार्गव के अलावा रो..सुनील गौतम, रो.संजय भार्गव, रो.नीरज कुमार, रो.मनीष एंड नीतू भार्गव, दीपक सिद्वांत आदि मौजूद थे।

डा.धीरज भार्गव ने जन्मदिन पर कुष्ठ आश्रम में बांटी खाने–पीने की चीजें

गाजियाबाद : रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर के चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव ने 4 जुलाई को अपने जन्मदिन पर हिंडन नदी स्थित कुष्ठ आश्रम में खाने–पीने की चीजों का वितरण किया। रोटरी क्लब के चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव, पूर्व प्रेजीडेंट रो.मनीषा भार्गव, कुनिका भार्गव व प्रतीक भार्गव बुधवार सुबह हिंडन स्थित कुष्ठ आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने आश्रम में रहने वाले 65 परिवार को खान–पीने की चीजें बांटी। कुष्ठ आश्रम में 100 किलो आटा, दाल, चावल,चीनी, छोले के अलावा तेल व फलों का वितरण किया। डा.धीरज भार्गव ने बताया कि कुष्ठ आश्रम में 65 कुष्ठ रोगियों का परिवार रहता है। इस दौरान कुष्ठ रोगियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए वे समय–समय पर आश्रम में खाने–पीने की चीजों का वितरण करते रहते है।

EDITORIAL

Kejriwal-Baijal tussle: The SC order puts the onus on AAP

For years now, Delhi's citizens have had to put up with the refrain that the problems that plague the city (and many do) can't be addressed by its elected government because the Lieutenant Governor won't allow it to. On Wednesday, a five-judge bench of the Supreme Court headed by the Chief Justice of India did its bid to resolve the impasse.

The apex court did not strike down a previous Delhi High Court verdict that gave the LG more powers. But it emphasised the need for collective responsibility – on the part of the LG and the ministers – for the effective administration of Delhi. The verdict lays down and interprets the broad constitutional contours governing the relationship between the LG and the elected government.

The Aam Aadmi Party's response to the judgement has been celebratory, but while the Supreme Court has acknowledged the primacy of the elected government of Delhi over the LG in the administration of the national capital, it is not as though it has handed the elected government untrammelled powers. The Centre, and, by extension, the LG, retains the power to legislate on the issues of land, law and order and police.

Still, the court has said the LG has to act on the aid and advice of the council of ministers and does not enjoy any independent decision-making power. Clearing the air surrounding the roles of the elected government and the LG, the court ruled that the "status of NCT of Delhi is sui generis, a class apart, and the status of the Lieutenant Governor of Delhi is not that of a Governor of a State, rather he remains an administrator, in a limited sense, working with the designation of Lieutenant Governor".

This reiteration of the constitutional scheme by the top court does not clarify everything, though. The five-judge bench has said that a smaller bench of two judges will decide on pending matters in which, because of a conflict between the government and the LG, resolution is pending. The Centre too, may seek a review of at least some parts of the ruling.

The seeds of this confusion between the LG and the elected government were sown by the 69 constitutional amendments in 1991 that created a legislative assembly and made a national capital of Delhi. While the idea of the amendment was to give a larger say to the people of Delhi in its governance, it gave rise to friction between the elected government and the LG. Another important ongoing issue is whether Delhi can be granted statehood. The bench categorically ruled out that option "under our present constitutional scheme". The elected government in Delhi may have more authority than it has had of late. But with power comes responsibility. It should have no further excuse to not get down to working on and finding solutions to problems that plague the capital.

-By Dr. Dheeraj Kumar Bhargava

समर्थन मूल्य और किसानों की दुविधा

मनीषा भार्गव

c/kkj को घोषित खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का एक बड़ा दांव है। इस घोषणा में चार–पांच महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं, जिसका विश्लेषण जरूरी है। पहली तो यह कि सत्तारूढ़ दल ने 2014 के चुनावी घोषणापत्र में यह लिखित वचन दिया था कि वह स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को सत्ता में आते ही लागू करेगी, जिसमें किसानों को सी–2 लागत (फसल की हर मद को जोड़ते हुए कुलजमा लागत) के ऊपर 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई थी। दूसरी बात, 2015 में जब इस संदर्भ में एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई, तब अपने जवाब में केंद्र सरकार ने एक शपथ पत्र दाखिल किया कि यह व्यावहारिक नहीं है और वर्तमान संसाधनों में संभव भी नहीं है। इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं– एक, चुनावी वादा एक अलग चीज थी, दूसरा, इसे लागू करने की इच्छा के बावजूद उपलब्ध संसाधनों में इसे पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए पूरे मामले ने यह मोड़ ले लिया कि पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया। बार–बार यह कहा जाता रहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट काफी पहले आ गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों पर बिल्कुल अमल नहीं किया गया। मगर सच है कि बाद में भी यह नहीं किया जा सका। अभी तक इस मामले में ज्यादा नहीं हो सका, तो अगले बजट में भी कुछ नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वह आचार संहिता से पहले का बजट होगा। हां, इस बार बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही जरूर गई, लेकिन उस वक्त अमल नहीं किया गया। कहा गया कि आगामी खरीफ से इस पर अमल होगा। इसलिए इस मौके पर उम्मीद बनना स्वाभाविक ही था। पहले आमतौर पर सी–2 लागत के ऊपर 10–12 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती थी। उसके मुकाबले सत्तारूढ़ दल ने 50 प्रतिशत की बात की, जिसकी चर्चा स्वामीनाथन आयोग में भी की गई है। मगर इन वर्षों में एक और चीज यह हुई है कि सी–2 लागत की परिभाषा ही बदल दी गई है। उसका नया बेंचमार्क नीचे कर दिया गया है। पिछले चार वर्षों में जितने समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं, उनमें केवल दो जिंसों यानी धान और गेहूं को छोड़कर सभी फसलों के बाजार मूल्य सभी आठों मौसम में समर्थन मूल्य के नीचे रहे हैं। जबकि समर्थन मूल्य की प्रतिबद्धता या आधार यह है कि यदि बाजार में समर्थन मूल्य के नीचे किसी जिंस की कीमत जाती है, तो सरकार किसी कीमत पर उस दाम को नीचे नहीं गिरने देगी और तय कीमत पर किसानों से खरीदेगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट में एक वाक्य सब बार–बार दोहराते हैं कि आशा की जाती है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचा मूल्य प्रायरू मिलता रहेगा। यदि ऐसी स्थिति आती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बाजार के भाव जाते हैं, तो सरकार उसकी खरीद के जरिए उतना भाव तो सुनिश्चत कराएगी ही। मगर इन चार वर्षों में यह भी नहीं मिला। यानी एक तो लागत का स्तर बदला गया, चार साल तक वादा पूरा नहीं किया गया, घोषित समर्थन मूल्य नहीं मिले, फिर अब किस आधार पर यह विश्वास किया जाए कि जो घोषणा की गई है, वह मूल्य किसानों को मिल जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में काम करता है। दरअसल, खेती की एक विशेष परिस्थिति है। उसका एक अलग स्वभाव है। सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले तमाम श्रमिकों व कुशल कार्यकर्ताओं को एक निश्चित रकम तय अवधि में मिलती रहती है। यानी उसकी आय का स्रोत लगातार प्रवाहित होता रहता है। मगर किसानों के नगदी–प्रवाह में दिक्कत है। जिस दिन से वह खेत जोतकर बुआई की तैयारी करता है, तब से लेकर जब तक फसल नहीं आ जाती, उसके दोतरफा व्यय चलते रहते हैं। यानी खेती पर भी खर्च होता है और घर–परिवार पर भी, जबकि उसको आय छह महीने के बाद होती है। इन तमाम खर्चों और आय की प्रतीक्षा में किसानों की सहनशीलता जवाब देने लगती है।

आतंक की जड़ पर प्रहार का वक्त

प्रियंका जैन

gekjk देश लंबे समय से पाकिस्तान–प्रायोजित आतंकवाद के दंश झेल रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम इसका तगड़ा प्रतिकार करें और पाकिस्तान को बता दें कि उसे अपनी नापाक हरकतों का खामियाजा भुगतना ही होगा। हम बीते कई वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि यह पड़ोसी मुल्क आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है और आतंकी हरकतों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हुआ क्या? अब तो लगता है कि पाकिस्तान के साथ–साथ पूरी दुनिया भी हमारी शिकायतों को तवज्जो नहीं दे रही है। हम चीन के समक्ष भी उस सड़क निर्माण परियोजना को लेकर पर्याप्त दमदार तरीके से विरोध नहीं जता सके, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरने वाली है कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन से जोड़ेगी। यदि हमारा रवैया ऐसा ही ढुलमुल बना रहा और हम स्थितियों को यूं ही स्वीकार करते रहे तो हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि दुनिया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी की हमारी मांग को गंभीरता से लेगी। अब तो भाजपा कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीपी) के साथ गठबंधन में भी नहीं कि उसे महबूबा मुफ्ती की बातों की परवाह करनी पड़े, जो हमेशा पाकिस्तान के प्रति सद्भावना दिखाने की बात करती रही हैं। हालांकि इसके बारे में काफी कुछ लिखा व कहा जा चुका है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम उन आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करें, जो आतंकियों को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं और कश्मीर में उनकी घुसपैठ कराते हैं। भारत जैसे विशाल आकार व रसूख वाले किसी भी देश को अपने हितों की सुरक्षा और सीमा पार आतंक को हमेशा के लिए रोकने के लिए यही करना चाहिए। हम लगातार उसी एक 'सर्जिकल स्ट्राइक का ढोल पीटते नहीं रह सकते, जो दो साल पहले पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई थी और जिसमें हम अपना लक्ष्य बखूबी साधने में सफल रहे थे। अब वास्तव में तमाम आतंक–प्रशिक्षण केंद्रों पर व्यापक रूप से औचक हमला करने की जरूरत है। हाल ही में पेरिस में हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक में पाकिस्तान को आतंकियों की फंडिंग रोकने में विफल रहने के कारण ग्रे लिस्ट यानी संदिग्ध देशों की सूची में डालने का फैसला किया गया। 37 सदस्य देशों वाले एफएटीएफ ने माना कि पाकिस्तान में निर्बाध ढंग से आतंकी समूह चल रहे हैं और पाकिस्तान सरकार आंख मूंदे बैठी है।

Front wheel hanging over edge, Noida school bus narrowly escapes plunge into canal

Ghaziabad : A major accident was averted on Wednesday morning when a school bus carrying 10 children almost went over bank of a canal with its left front wheel hanging over the edge in Jewar area of Greater Noida. According to eyewitnesses, the incident took place around 7.30am on the Rabupura-Jewar route when the driver of the school bus lost control of the bus on the muddy road near the canal. The bus came to a halt at the brink of the canal, with its front wheel hanging over the edge. The bus belonged to Agrasen Public

School in Dayanatpur village of Jewar Kasba in Greater Noida."The bus was on its way towards Nagla Basona village in Jewar from Sigara village in Rabupura after picking up students from their residences. On the Rabupura to Jewar route, there is a muddy patch of road alongside the canal. A buggy was coming from the opposite side and the driver swerved the bus to the left to give way to the buggy. However, the muddy road alongside the canal collapsed under the weight of the bus," Navneet Goyal, managing director, Agrasen Public School, Jewar, said. Children, aged between 12 and 14 years, were rescued from the bus by bystanders. The bus was then pulled back from the canal. "We have all the documents of our buses in place," Goyal said, adding that no one was injured in the accident. "No one was injured. We brought all students to school safely and classes continued as usual," Goyal said. Police said that no case was registered in the matter. "By the time a police team reached the spot, the bus had already been pulled back and was on its way to the school. No case was registered as there was no accident," said SS Bhati, station house officer, Jewar police station. Jewar MLA?Thakur Dhirendra Singh also took cognizance of the incident on social media and said,"We expect action against irresponsible officers and contractors. Those responsible for putting lives in danger should be severely dealt with (sic)."

Temple? Burari wonders what to do with 'house of death'

Delhi : The Burari house in which 11 members of a family were found dead on Sunday stares at an uncertain future with a a few locals suggesting that a temple should replace the building. The deaths left many residents scared, a few tenants in the alley are contemplating relocation and local businesses are suffering because of the continued police presence. The neighbourhood continued to attract curious passersby even on Thursday as they would stop their vehicles to discuss the deaths and take photographs.

GZB family in Maruti 800 hit by speeding Honda City on EP expressway, one killed

Ghaziabad : One person was killed and six members of his family injured after their car was hit by a speeding Honda City sedan on the Eastern Peripheral Expressway (EPE) near Masuri, late on Sunday. The police identified the dead man as 28-year-old Rajesh Kumar. His wife Geeta and four minor children suffered injuries. The couple, their three children and another four children of Kumar's brother were enjoying a drive on the EPE in their Maruti 800 when the accident took place. "While they were taking a U-

turn to return home, a speeding Honda City hit their car from behind," Sanjay Kumar, Kumar's brother-in-law, said. Kumar owned a battery making factory in Lal Kuan, Ghaziabad, and the family is from Dasna town under the Masuri police station area. "His wife was discharged from the hospital while two children are still in the hospital. The Honda City occupants escaped with minor injuries as the air bags deployed on impact. We have filed a police complaint in the incident," Sanjay said. Both the damaged cars were brought to the Masuri police station. "We have filed an FIR against the driver of the Honda City. The occupants fled leaving the car behind after the accident. We will trace them with the help of the car's registration number," Umesh Bahadur Singh, SHO of Masuri police station, said. The police said the FIR was filed under the IPC sections of 304a (causing death of any person by a rash or negligent act), 338 (causing grievous hurt) and 279 (rash and negligent driving endangering lives). Accident have been frequent on the newly opened expressway. A cyclist was killed by a speeding Brezza near the Duhai interchange in Ghaziabad on June 9. On June 1, five cattle died after being hit by speeding vehicle on the expressway in Ghaziabad. On June 4, a scooter rider slipped and died near the Duhai interchange.

Police yet to arrest Haryana BJP leader's son booked for rape

Ghaziabad : Three days after a 27-year-old woman alleged that she was raped by the son of a Haryana Bharatiya Janata Party (BJP) leader, police are yet to arrest the accused. According to the victim, the accused Uday Veer Singh Tanwar, son of Rao Surendra Singh, a leader from Kaithal, took her to Manali, Himachal Pradesh, along with two of his friends on June 12 and raped her on June 14. She also claimed that she was raped for the first time on June 1 after being drugged. The victim approached the police with a complaint on June 30 and, based on her statement, a case of rape and unnatural sex was registered against Tanwar. Two of Tanwar's accomplices, Radhika Agarwal and Yash Saarda, were arrested on July 2 from their rented house in Noida's Sector 47 for allegedly blackmailing the victim by recording her video. "Both the arrested persons were released on bail on Tuesday. We have formed teams to nab Uday Veer and we are tracking his mobile phone number. If the need arises, a team will also be sent to Kaithal to arrest him. He has been charged under the Indian Penal Code sections 376 and 377 for rape and unnatural sex," Avnish Dixit, station house officer, Sector 49 police station, said. Police are also probing the victim's claims that she was forcibly given psychotropic drugs and later asked to buy marijuana. "It has come to light that the accused and his friends were using drugs. We are also probing the matter," Shwetabh Pandey, circle officer 3, Noida, said. Tanwar, a resident of Kaithal in Haryana, is believed to be aged between 20-23 years. He is enrolled in a private university in Noida and is living in a rented house in Sector 47. The victim, who is 27-years-old, is married and lives in Noida. According to the victim's complaint, Tanwar met her on June 1 through a friend at a party. The woman further said that she was raped at Tanwar's residence in Sector 47 on June 1 after being drugged. "After June 1, he and his friends started blackmailing me with a video they had shot of me. Uday Veer then forced me to go to Manali with his friends where I was asked to pay the bills. He had unnatural sex with me on June 14 in Manali and I somehow reached Delhi after the incident. On June 18, he came to my house and threatened to kill me if I revealed the incident to anyone," the woman said in her complaint.

Kejriwal meets Delhi L-G, says Centre not obeying Supreme Court order

Delhi : The tussle between Delhi lieutenant governor Anil Baijal and the Aam Aadmi Party government seems to have taken a new turn on Friday as chief minister Arvind Kejriwal indicated that some differences including the jurisdiction over the services department are yet to be ironed out. Kejriwal and his deputy Manish Sisodia met Baijal seeking his cooperation in Delhi's development and good governance on Friday, two days after the Supreme Court ruled that the central representative was bound by the constitution to listen to the national capital's democratically elected government. "Met L-G today, Mr Anil Baijal refused to agree that services department has come under the elected government in Delhi. He said that the 2015 MHA order on services dept has not been quashed by the Supreme Court," he told mediapersons. In a letter to Kejriwal, Baijal pointed to a 2015 ministry of home affairs (MHA)?notification, issuing "presidential directions" under Article 239 and 239AA of the Constitution. It said 'services' falls outside the purview of the Legislative Assembly of the NCT of Delhi and consequently the government of the National Capital Territory of Delhi will have no executive powers in relation to 'services'. "The said notification was also upheld by the high court of Delhi in its judgement on August 4, 2016," he said.

Ghaziabad Police arrest man for allegedly killing landlord's son over affair with his mother

Ghaziabad : Police arrested a 30-year-old man on Thursday for allegedly kidnapping and killing a 14-year-old boy, whose body was found with his throat slit at a sugarcane field in Muradnagar, nearly eight kilometers away from his house in Ghaziabad's Modi Nagar on June 29 morning. According to the police, the accused, Subhash Kumar, was living as a tenant in the boy's house for the past nine months. Kumar killed the boy fearing that he would spill the beans about Kumar's alleged affair

with the victim's mother. "Initially, the boy's family, in their FIR, had suspected the role of some boys of his locality as they had a fight while playing cricket on June 28 afternoon," said Vaibhav Krishna, senior superintendent of police (SSP), Ghaziabad. During the initial investigation, the police questioned the boys but they had no clue about the murder. Further, the brutality of the murder pointed towards the involvement of some adult. The SSP said that involvement of the boys aged 7 to 13 years, who had a fight with the victim recently, was thus ruled out. "However, the investigation revealed that Kumar had relations with the boy's mother and they both were seen together by the boy in Kumar's room on June 26," the SSP said. Later, while scanning the CCTV footage from Modinagar (boy's locality) to Muradnagar on the Delhi-Meerut Road, the boy was seen riding pillion with Kumar on a scooty. "Kumar had offered to purchase kites for the boy. In another CCTV footage, Kumar is seen near the Ganga Canal and taking turn towards Jalalabad. He's seen carrying a jute bag and a knife. The boy was taken to an isolated sugarcane field. Kumar first strangulated the boy and then slit his throat," the SSP said. Kumar, who works as supervisor with an LPG agency in Ghaziabad, is married with three children.

Lucknow interfaith couple's passports cleared

Noida : The passport issued by the Regional Passport Office (RPO) in Lucknow to an inter-faith couple is valid, and an official and police had gone beyond their brief on the matter, an internal probe of the ministry concluded. The matter had raised a storm last month when the official in question was transferred, with external affairs minister, Sushma Swaraj, being trolled. "The passports of Tanvi Seth and Anas Siddiqui have been cleared," Regional Passport Officer (RPO), Piyush Verma, said on Wednesday. Persons familiar with the internal probe of the ministry said an official at the RPO and police in the verification report went beyond their brief, getting into details that are "irrelevant" while issuing the travel document. The couple had alleged harassment by a passport official, saying they were targeted because of their interfaith marriage. The UP police, in its verification report, made remarks that Seth was not staying in the address in Lucknow which was given at the time of applying for the passport. But the probe report found that the police verification report, according to new rules, shouldn't have gone beyond two points of inquiry:

Only 12 sitting judges out of 23 have disclosed assets on Supreme Court website

Noida : Almost a decade after the Supreme Court passed a resolution to make public the details of assets owned by the apex court judges, only half of the sitting judges have disclosed their assets and investments on the top court's website. Of the 23 sitting judges in the Supreme Court, only 12 have so far disclosed their assets on the apex court website. Chief Justice Dipak Misra and the next four senior-most judges, Justices Ranjan Gogoi, M B Lokur, Kurian Joseph and A K Sikri are among those who have declared their assets. Justices S A Bobde, N V Ramana, Arun Mishra, A K Goel, R Banumathi, A M Khanwilkar and Ashok Bhushan have also disclosed their assets and liabilities along with that of their families. The apex court website does not have the names of Justices R F Nariman, A M Sapre, U U Lalit, D Y Chandrachud, L Nageswara Rao, Sanjay Kishan Kaul, Mohan M Shantanagoudar, S Abdul Nazeer, Navin Sinha, Deepak Gupta and Indu Malhotra in the list of those who have disclosed their assets, liabilities and investments.

Stubble burning in north India pollutes central and southern states too, says NASA study

Delhi : Pollution from burning agricultural waste or crop residue by farmers in the north-western states of India not only impacts air quality in Delhi and the neighbouring areas but also affects central and southern Indian states and the eastern parts of the Indo-Gangetic Plains (IGP), a new study has revealed.The study, led by NASA's Goddard Space Flight Center, has found that fine black carbon particles released from biomass burning in Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh between October and November reaches parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, and Odisha in the post-monsoon and winter seasons, with the highest impact being observed in the first and second weeks of November. Researchers attributed the rise in and dispersal of pollutants far from the source to mechanised harvesting practices, which leave 10-30cm-high stubble in the field, and prompt farmers to burn what's left."Mechanised harvesting leaves more residue in the field, in the form of stalks, stubbles, and straws that are burnt by farmers to clear the field for the next crop," said RP Singh, co-author and professor at the School of Life and Environmental Sciences, Schmid College of Science and Technology, Chapman University, US. "An increase in crop residue burning is the result of increased shift towards mechanised harvesting, which has spread gradually to other states, including the foothills of the Himalayas."Black carbon, commonly known as soot, is emitted during incomplete biomass burning and vehicular combustion, and has a negative impact on health, climate, rainfall, and soil productivity. These particles are so fine (0.1 to 1 micron) that they can disperse over large distances; in humans they can cross cell walls and affect health. Their ability to absorb heat from sunlight also makes these pollutants the second-most warming agent in the atmosphere, after carbon dioxide.

हेल्प लाईन नंबर

गाजियाबाद प्रशासन

डीएम -	2824416
आवास -	2820106
एडीएम (सिटी) -	2828411
एडीएम (प्रशासन) -	2827016
सिटी मजिस्ट्रेट -	2827365
आयकर विभाग -	2714144
पासपोर्ट कार्यालय -	2721779

पुलिस अधिकारी

एसएसपी -	2821120, 2820157
पुलिस अधीक्षक नगर -	2854015
पुलिस अधी. यातायात -	2829520
क्षेत्राधिकारी प्रथम -	2733070
क्षेत्राधिकारी द्वितीय -	2791769
क्षेत्राधिकारी तृतीय -	9958776662
क्षेत्राधिकारी चतुर्थ -	2898131
साहिबाबाद -	2630691
कविनगर -	2711843
लिंकरोड़ -	2770310
इंदिरापुरम -	2275858
लोनी -	2600097

जीडीए

उपाध्यक्ष जीडीए -	2791114
जीडीए सचिव -	2790891

अस्पताल

सी.एम.ओ. -	2710754
सी.एम.एस. -	2730038
आपातकालीन -	2850124
कोलम्बिया एशिया -	3989896
यशोदा अस्पताल -	2750001-04
गणेश अस्पताल -	4183900
संतोश अस्पताल -	2741777
सर्वोदय अस्पताल -	2701694
जि0 अस्पताल(एम्बुलेंस) -	2730038

नरेन्द्र मोहन अस्पताल (एम्बुलेंस) 2735253
यशोदा अस्पताल (एम्बुलेंस) 2701695
पुष्पांजली क्रांसले हॉस्पिटल 4188000
पुष्पांजली मेडिकल सेन्टर 43075600

बीएसएनएल

आदेश कुमार (जीएम) -	2755777

अग्निशमन विभाग

नगर कन्ट्रोल रूम -	2734906
कन्ट्रोल रूम-कोतवाली -	2732099
जिला कन्ट्रोल रूम -	2766898

पुलिस स्टेशन

कोतवाली -	2732088
सिहानी गेट -	2791627
कविनगर -	2711843
विजयनगर -	2740797
लिंकरोड -	9999993066
इंदिरापुरम -	2902858
साहिबाबाद -	9999993020
लोनी -	2600097
अग्निशमन विभाग -	2732099
	9818702101
रेलवे इन्कवायरी -	131

नगर निगम

नगरायुक्त -	2790425, 2713580

विद्युत विभाग

मुख्य अभियंता -	2821025

पूछताछ

रेलवे कस्टमर -	2797840, 139
रिजर्वेशन -	8888
रोडवेजइन्कवायरी -	2791102

प्रेस विज्ञप्ति, समाचार, विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।
Phone No.: 0120-2850800, 2850297

जल्द ही शहर की सड़कों पर दौड़ेगी 200 ई–रिक्शा

गाजियाबाद : आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के लिए एक निजी कंपनी शहरी क्षेत्र में 200 ई–रिक्शा चलाएगी। कंपनी ने जीडीए को प्रस्ताव दिया है। साथ ही 30 चार्जिंग एवं बेटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह मांगी है। जिसके एवज में वह किराये का भुगतान करेंगे। यह भी बताया है कि उन्होंने सर्वे किया है। जल्द ही ई–रिक्शा चलाने के लिए मुफीद रूट निर्धारित किए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर जीडीए में मंथन चल रहा है। कंपनी ने जीडीए अधिकारियों को बताया कि इससे रोजगार बढ़ेगा। बेरोजगारों को किस्तों पर ई–रिक्शा चलाने को दिए जाएंगे। हर महीने उनसे मामूली किराया लिया जाएगा। जब कीमत जितना किराया मिल जाएगा तो ई–रिक्शा हमेशा के लिए चालक को दे दिया जाएगा। ऐसे में बेरोजगारी कम होगी। ई–रिक्शा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो उसे चार्ज होने में घंटों लगते हैं। कंपनी का कहना है कि वह ई–रिक्शा की बैटरी डिस्चार्ज होने पर दो मिनट में उसे चार्ज बैटरी से बदल देंगे। जिससे चालक को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। उसका कामकाज प्रभावित न हो। बाद में डिस्चार्ज बैटरी को चार्जिंग पर लगा दिया जाएगा।

15 हजार परिवार को मिली पीएनजी की सुविधा

गाजियाबाद : इंदिरापुरम के न्याय खंड में रहने वाले करीब 15 हजार परिवारों को पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। इससे लोगों को काफी राहत महसूस होगी। पार्षद मीना भंडारी ने बताया कि यहां पर पीएनजी की सुविधा न होने से लोगों को काफी परेशानी थी। सिलेंडर आने में लंबा समय लगता था। लोगों की समस्या को देखते हुए आइजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से गैस पाइपलाइन डाली गई है। इसमें स्थानीय सांसद वीके सिंह का विशेष सहयोग रहा।

भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों को दिखाया जाएगा जोन से बाहर का रास्ता

गाजियाबाद : सरिया माफिया से सांठगांठ रखने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई को लेकर डीजीपी द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों पर पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। पुलिस सरिया माफिया से संबंध रखने वाले पुलिसकर्मियों की सूची मेरठ जोन के एडीजी को भेजने की तैयारी कर रही है। इसके बाद एडीजी द्वारा इन सभी पुलिसकर्मियों को जोन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग में काम भी शुरू कर दिया गया है। एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि शुरुआती जांच में जनपद के दो इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर की सरिया माफियाओं से सांठगांठ पाई गई थी। हालांकि इसके पुख्ता तौर पर सबूत नहीं मिले थे। बावजूद इसके तीनों लोगों के नाम एडीजी मेरठ जोन के दफ्तर में भेजे जाएंगे। इन इंस्पेक्टर में कविनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी समरजीत डक्षसह और विजयनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी नरेश कुमार सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा लालकुआं चौकी के तत्कालीन चौकी प्रभारी बीनू सिंह का नाम भी एडीजी दफ्तर भेजा जाएगा। बता दें कि मई माह में एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने सरिया चोरी के माफिया के खिलाफ रात भर का अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की थी।

पार्क की जमीन पर कब्जा, जीडीए नहीं कर रहा कार्रवाई

गाजियाबाद : नेहरू नगर के ई–ब्लॉक के पार्क पर अवैध कब्जा है। पार्षद राजेंद्र त्यागी ने जीडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की कई जमीनें अवैध कब्जे में हैं। शासन को शपथ पत्र में लिखित रूप में यह जानकारी देने के बावजूद जीडीए पार्क को खाली नहीं करा पाया है। उन्होंने इस संबंध में कमिश्नर से शिकायत की है। जीडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग, यूपीएसआइडीसी समेत कई विभागों की भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। पार्षद राजेंद्र त्यागी आरडीसी स्थित होटल कृष्णा सागर में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे।

लाखों ठगने वाली युवती गिरफ्तार

गाजियाबाद : कविनगर थाना पुलिस ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना व विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी की रकम एडवांस में दिलाने और विधवा पेंशन के नाम पर ठगी करने वाली युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ एक दर्जन से अधिक लोगों ने ठगी की शिकायत की थी। कविनगर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने आरोपित महिला हापुड़ के पिलखुआ निवासी नेहा त्यागी है। उसके खिलाफ आकाश नगर डासना के रहने वाले कपिल सिरोही समेत कई लोगों ने शिकायत दी थी। जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि नेहा लोगों से प्रधानमंत्री आवासीय योजना, आवास–विकास की योजना और नौकरी दिलाने समेत कई प्रलोभन देकर रकम ऐंठती थी। वह एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपये की ठगी भी कर चुकी है। इसके अलावा कई विधवा महिलाओं से उसने पेंशन दिलाने के नाम पर ठगी की। आरोपित द्वारा दिए गए चेक बाउंस होने पर मामले का पर्दाफाश हुआ। पहले नेहा ने 30 जून तक रकम लौटाने की बात कही, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले तो लोगों ने शिकायत कर दी। सीओ द्वितीय आतिश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस को सामूहिक तहरीर मिली थी। इसमें दिनेश शर्मा से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 8500 रुपये ठगे। आरोप है कि नेहा ने मुलाकात के दौरान उनका एटीएम चोरी कर लिया और उनके कार्ड से 25000 रुपये भी निकाल लिए। संतोष देवी से 22000 रुपये, पवन कुमार से 30000 रुपये, विमल कुमार से 28000 रुपये, बबीता से 22000 रुपये, रवि शर्मा से 5500 रुपये और सुमन रावत से 175000 रुपये की ठगी की गई है। सभी से आवास–विकास की योजना के नाम पर नेहा ने रकम ऐंठी। इतनी शिकायतों के बाद मामले की गंभीरता से जांच की गई। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपित महिला को गिरफ्तार किया गया।

1958 लोग का जल्द पूरा होगा अपने मकान का सपना

गाजियाबाद : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वर्ग के 1958 लोग जल्द अपना मकान बना सकेंगे। डूडा ने इतने लोगों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिले ही धनराशि की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। 30 वर्ग मीटर तक की भूमि का मालिकाना हक रखने वाले तीन लाख रुपये तक सालाना आय वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ढाई लाख रुपये अनुदान की योजना है। तीन किस्तों में यह भुगतान होता है। पहली किस्त 50 हजार रुपये की होती है। दूसरी डेढ़ लाख और तीसरी 50 हजार रुपये की होती है।

आरटीओ विभाग में दस जुलाई तक शुरू होगी ई–फाइलिंग

गाजियाबाद : आरटीओ विभाग में ई–फाइलिंग की व्यवस्था लागू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पहले यह व्यवस्था दो जुलाई से लागू होनी थी लेकिन अब दस जुलाई तक ई–फाइलिंग शुरू हो जाएगी। इसके जरिए डीलर प्वाइंट से गाड़ी के दस्तावेज आरटीओ ऑफिस ऑनलाइन भेजे जाएंगे। जहां गाड़ी नंबर और आरसी जारी करने की कार्यवाही जल्द हो सकेगी। अभी तक वाहन डीलर वाहनों की फाइल बनाकर आरटीओ दफ्तर में पहुंचाते थे। इस बारे में एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि ई–फाइलिंग को लेकर छह जून को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और आयोजित किया जाना है। ई–फाइलिंग के तहत डीलर प्वाइंट से ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अधिकारी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई दस्तावेज अगर गलत मिलता है तो डीलर के मोबाइल पर मैसेज और ई–मेल से इसकी जानकारी दी जाएगी। व्यवस्था के तहत पंजीयन अधिकारी द्वारा सिस्टम पर ही दस्तावेजों को अप्रूव कर वाहन की पंजीयन संख्या आवंटित करते हुए पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई–फाइलिंग लागू होने से आरसी जारी होने और गाड़ी नंबर आवंटित करने में समय कम लगेगा।

जीडीए ने हैबिटेट सेंटर किया सील, 49 करोड़ रूपये बकाया

गाजियाबाद : इंदिरापुरम के अहिंसा खंड स्थित हैबिटेट सेंटर को बुधवार को जिला प्रशासन और जीडीए ने सील कर दिया। तकरीबन 49 करोड़ रुपये बकाया राशि नहीं चुकाने पर कार्रवाई की गई। टीम ने सभी गेटों और सेंटर प्रबंधन के दोनों सेल्स ऑफिस पर सील लगा दी। नोटिस चस्पा करते हुए प्रबंधन और हैबिटेट सेंटर की सिक्योरिटी को निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति की एंट्री पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से करीब सौ दुकानें और 12 रेस्टोरेंट भी बंद हो गए। हैबिटेट सेंटर प्रबंधन जीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।

विद्युत विभाग का कहना जिले में पांच प्रतिशत लोग करते है बिजली चोरी

गाजियाबाद : विद्युत निगम के एक सर्वे के मुताबिक गाजियाबाद जिले में 95 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और समय पर अपने बिल का भुगतान करते हैं। इन उपभोक्ताओं का लोड भी सर्वे के दौरान सही पाया गया है जबकि पांच प्रतिशत उपभोक्ता जिले में बिजली चोरी करने में सामने आए हैं। विभाग ने सर्वे के दौरान अधिक बिजली चोरी वाले क्षेत्रों को चिह्नित भी किया है। अधिकारियों का दावा है कि अगर शेष पांच प्रतिशत उपभोक्ता चोरी की बिजली न चलाएं और समय पर बिल का भुगतान करें तो जिले में विद्युत दरों को भी कम किया जा सकता है। विद्युत निगम बिजली चोरी रोकने और बकाया वसूली के लिए इन दिनों मास रेड अभियान चला रहा है। बकाया वसूली में विभाग को सफलता मिल रही है लेकिन बिजली चोरी पर तमाम कोशिशों के बावजूद रोक नहीं लग पा रही है। जिले में विद्युत निगम का उपभोक्ताओं पर करीब 152 करोड़ रुपया बकाया है। वसूली में सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है। सर्वे में सामने आया है कि पांच प्रतिशत क्षेत्रों में बिजली चोरी हो रही है। इसमें नंदग्राम, भोवापुर, कैला भट्टा, प्रताप विहार और विजयनगर के कुछ क्षेत्र, रईसपुर, लोनी के कुछ गांव शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मीटर न लगवाने में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है।

RC OF इंदिरापुरम गैलोर ने शैमरॉक देव ड्राप्स स्कूल में लगाए पौधे

नोएडा : नोएडा सेक्टर–116 स्थित शैमरॉक देव ड्राप्स प्ले स्कूल में रविवार को रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने पौधारोपण किया। इस दौरान बेबी शो का भी आयोजन किया गया। क्लब द्वारा 60 अभिभावकों को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। पौधारोपण की शुरूआत मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक गवर्नर नोमिनी 3012 रो. आलोक गुप्ता ने की। क्लब के अध्यक्ष रो.अंकित धारिया ने बताया कि स्कूल में नीम, अनार, गुलधर, नींबू आदि के 25 पौधे लगाए गए। जिनकी देखदेख की जिम्मेदारी बच्चों ने ली। मुख्य अतिथि ने कहा कि जिस तरह से आज पेड़ों की कटाई हो रही है। ऐसे में हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे अवश्य लगाने चाहिए। पौधों से न केवल पर्यावरण संतुलित होता है बल्कि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है। इस दौरान बेबी शो का भी आयोजन किया गया। बेबी शो में आए 60 अभिभावकों को क्लब द्वारा तुलसी के पौधे भेंट किए गए। पौधारोपण कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष रो.मनीषा भार्गव, चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव, खुशहाल चौपड़ा, डौली चौपड़ा व स्कूल के टीचर व प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

वसुंधरा सेक्टर–12 में रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने लगाए पौधे

साहिबाबाद : रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने बृहस्पतिवार को वसुंधरा सेक्टर–12 में 20 पौधे लगाए और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। क्लब द्वारा एक सप्ताह पूर्व भी दो दर्जन पौधे लगाए गए थे। इस दौरान क्लब द्वारा लोगों को तुलसी के पौधे भी भेंट किए गए। पौधारोपण की शुरूआत मुख्य अतिथि असिस्टेंट गवर्नर जोन–16 रो. सुनील गौतम ने की। वसुंधरा सेक्टर–12 स्थित को–ऑपरेटिव सोसायटी के गेट नंबर–दो पर रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर के चार्टर प्रेजीडेंट डा. धीरज भार्गव, आईपीपी रो.मनीषा भार्गव, कुनिका भार्गव, प्रतीक भार्गव, संजय शर्मा, विक्रम, प्रियंका जैन, रोबिन, राहुल व रिंकी आदि ने पौधारोपण किया। चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज भार्गव ने बताया कि इस दौरान गुलाब, सफारी सहित विभिन्न तरह के 20 पौधे लगाए गए। जिनकी देखभाल भी रोटरी क्लब द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज पेड़ों की कटाई हो रही है। ऐसे में हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे अवश्य लगाने चाहिए। पौधों से न केवल पर्यावरण संतुलित होता है बल्कि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है।

रोटरी क्लब द्वारा की जाएगी पौधों की देखभाल, एक सप्ताह पूर्व भी लगाए थे पौधे

BUREAU OFFICE
PRATEEK BHARGAVA
Bureau Chief
5, Ashok Vihar, 3rd Floor,
GMS Road, Nr. Ballupur
Chowk, Dehradun.
Mobile: +91 8130640011
Email: prateekb@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release and Advertisements

BUREAU OFFICE
VIKRAM KUMAR
Bureau Chief
12/516, Friends Co-operative
Society Vasundhra,
Ghaziabad (UP)
Mobile: +91 8130640077
Email: vikram@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release and Advertisements

Printed and Published by Dheeraj Kumar Bhargav at B.F.L Inrotech Ltd, C-9, Sector-3 Noida, Distt. Gautam Budh Nagar and Published at 282, Sarai Nazar Ali, behind MMG Hospital Ghaziabad (U.P.) 201 001. Editor: Dheeraj Kumar, Resident Editor : Manisha Bhargava** Email: editor@tbam.co.in **(RNI. No) : UPBIL / 2009 / 28691 Postal Registration No. UP/GBD-80/2016- 18.** Advertisement : Ph. No. : 0120-2850800, 2850297, Fax : 0120-4561000 at 67, 1st Floor, Richpal Puri, Hapur Road, Ghaziabad (U.P.)** Responsible for selection of News under the PRB Act. Reproduction in any manner, electronic or otherwise in whole or in post without prior written permission is prohibited.